

Bihar Administrative Service Association

(Registration No-633/2003)

Shashank Shekhar Sinha
President

Mob. No.-9334118192



Sunil Kumar Tiwary
General Secretary

Mob. No.- 9431085120

Vice President

Ajay Kumar

9835737317

Subodh Kumar

7979919465

Joint Secretary

Chandrashekhar Azad

8987044905

Vikash Kumar

7717770977

Treasurer

Shashi Shekhar

9334557086

Memo No 38

Date 16.08.2023

सेवा में,

प्रधान सचिव,

सामान्य प्रशासन विभाग,

बिहार सरकार, पटना ।

विषय:— बिहार सरकार द्वारा 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित बिहार प्रशासनिक सेवा के ऐसे पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति की रिक्ति एवं प्रकाशित विज्ञापन की तिथि उक्त नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होने से पूर्व तिथि का होने के कारण भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप निर्णय लेते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने से संबंधित पुनः अनुरोध किए जाने के संबंध में ।

प्रसंग:—

- (1) भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi के Office Memorandum no.- 57/05/2021-P&PW (B), Dated-03.03.2023 (अनुलग्नक 1)
- (2) भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training के निर्गत पत्र संख्या

(2)

No. 25011 /02 /2021 -AIS -II (Pension), Dated
13.07.2023 (अनुलग्नक 2)

(3) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के आदेश संख्या-1/
पेन- 1001 /2023-सा0प्र0-14593, दिनांक 01.08.2023

(अनुलग्नक 3)

(4) बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा किया गया अनुरोध पत्र
संख्या 27, दिनांक 12.04.2023

(अनुलग्नक 4)

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों / आदेशों के साथ अनुरोधपूर्वक कहना है कि वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या-1964, दिनांक 31.08.2005 के द्वारा आदेश निर्गत हुआ कि दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को नई पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित किया जायेगा (अनुलग्नक 5)। इसी क्रम में दिनांक-01.09.2005 के बाद नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भी नई पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित किया गया है ।

(2) इस संबंध में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अनुरोध पत्र संख्या 27, दिनांक 12.04.2023 द्वारा पूर्व में भी बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भारत सरकार के द्वारा निर्गत उक्त निर्णय के अनुरूप निर्णय लेते हुए पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने का अनुरोध किया गया था ।

(3) सुलभ प्रसंग हेतु पुनः भारत सरकार से निर्गत उक्त पत्र एवं निर्णय तथा बिहार सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के

(3)

पदाधिकारियों के संबंध में निर्गत अधिसूचना के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) से लाभान्वित करने के निम्नलिखित आधार का उल्लेख किया जाना आवश्यक है :-

(i) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों हेतु चिन्हित रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 03.02.2004 (दैनिक जागरण) (अनुलग्नक 6) एवं दिनांक-05.11.2004 (Times of India) (अनुलग्नक 7) को किया गया था ।

(ii) इस क्रम में दिनांक 03.02.2004 के दैनिक जागरण समाचार पत्र में 46वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका-6 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री दिनांक-31.03.2004 के पूर्व की तथा दिनांक-14.12.2004 को हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण सहित अन्य समाचार पत्रों में 47वीं संयुक्त (प्रा0) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका - 6 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री दिनांक-01.08.2001 के पहले की होनी चाहिए जिसे बाद में 31.12.2004 तक औपबंधिक रूप से कट-ऑफ डेट निर्धारित किया गया ।

(iii) उक्त विज्ञापनों के आधार पर दिनांक-18 जून, 2007 को 46वीं बैच के चयनित पदाधिकारियों की अधिसूचना बिहार गजट (अनुलग्नक-8) में प्रकाशित की गई तथा 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक-24.01.2009 (अनुलग्नक-9) को प्रकाशित किया गया ।

(4)

(iv) उपरोक्त (अनुलग्नक-6), 46वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका-1 में अधिकतम उम्र सीमा दिनांक-01.08.2000 तथा (अनुलग्नक-7), 47वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका-1 में अधिकतम उम्र की गणना दिनांक-01.08.2001 के आधार पर किया जाना स्पष्ट किया गया है ।

(v) इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि 46वीं एवं 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन, चयन की अधिसूचना तक कहीं भी नई पेंशन योजना से उक्त रिक्तियों को आच्छादित किया जाना स्पष्ट नहीं किया गया है अर्थात् उक्त दोनों 46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारीगण दिनांक-01.09.2005 के पहले के प्रचलित पेंशन नियमावली के आलोक में ही विज्ञापन प्रकाशित की गयी है ।

(4) इस संबंध में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा अपने पत्र संख्या-21, दिनांक-13.07.2021 द्वारा भी प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार को C.W.J.C. संख्या-10901/2006 मो0 क्यूमउद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार (अनुलग्नक-10) वाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-03.08.2011 को पारित आदेश :-

It is infact this aspect of matter which would clinch the issue in favour of the petitioners in as much as it is well settles by now that old vacancies have to be Government by the old rules coming into force after beginning of process of selection as per old rules can

(5)

not be made applicable के आलोक में— "नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के पूर्व नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त किए गए पदाधिकारियों / कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाय ", अनुरोध किया गया था ।

(5) नई पेंशन योजना के संबंध में भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi के Office Memorandum no 57/05/2021-P&PW(B), Dated 03.03.2023 के द्वारा एक अधिसूचना निर्गत किया गया है कि वैसे सरकारी कर्मी जिनकी नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22.12.2003 या उसके पूर्व निर्गत हो, लेकिन उनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार के अधीन 01.01.2004 से लागू नई पेंशन योजना (NPS) के बाद हुई हो, उनको भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) से लाभान्वित किया जाएगा तथा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके कंडिका 4 में उल्लिखित प्रावधान निम्नवत है :-

The matter has been examined in consultation with the Department of Financial Services, Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of the Courts in this regard. It has now been decided the, in all cases where the Central Government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised/notified for recruitment/appointment, prior to the date of notification for National Pension System i.e 22.12.2003 and is covered under the National

(6)

Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given a one-time option to be covered under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021). This option may be exercised by the concerned Government servants latest by 31.08.2023.

(6) उक्त अधिसूचना के आलोक में भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training के निर्गत पत्र संख्या No. 25011/02/2021-AIS-II (Pension), Dated 13.07.2023 द्वारा सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अखिल भारतीय सेवा के ऐसे पदाधिकारीगण जिनकी नियुक्ति हेतु रिक्ति एवं विज्ञापन नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होने की तिथि से पूर्व का है, को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में विस्तृत निर्णय एवं दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है ।

(7) उपरोक्त निर्णयों के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के आदेश संख्या -1/ पेन- 1001/2023 -सा0प्र0 -14593, दिनांक 01.08.2023 द्वारा दिनांक 22.12.2003 से पूर्व के प्रकाशित सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित अधिसूचना की तिथि के आधार पर कुल 11 भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को उक्त लाभ दिए जाने का आदेश निर्गत किया गया है ।

(8) इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि C.W.J.C. संख्या-2312/2022 बिहार प्रशासनिक सेवा संघ बनाम बिहार सरकार वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया है जो प्रक्रियाधीन है (अनुलग्नक-11) । विदित हो कि इस वाद में मुख्य सचिव, बिहार सरकार, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, प्रधान

(7)

सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार लोक सेवा आयोग, महालेखाकार, बिहार एवं अन्य को पक्षकार बनाने पर भी इस वाद में बिहार सरकार की तरफ से मात्र सहायक निदेशक, सामान्य भविष्य निधि के द्वारा प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है जिसमें माननीय विभिन्न न्यायालयों के न्यायादेश एवं भारत सरकार के उक्त निर्णय तथा परिपत्रों को समाहित / संदर्भित नहीं किया जा सका है । उक्त प्रतिशपथ पत्र में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि नई अंशदायी पेंशन योजना बिहार सरकार के द्वारा लागू किए जाने के पश्चात उक्त पदधिकारियों की नियुक्ति हुई है इसलिए इन्हें सामान्य भविष्य निधि का खाता संख्या प्राप्त नहीं कराया जा सकता है । स्पष्ट है कि यह विषय नियुक्ति की तिथि नहीं बल्कि रिक्ति एवं विज्ञापन की तिथि नई अंशदायी पेंशन योजना लागू किए जाने से पूर्व का होने की स्थिति में लिए गए भारत सरकार के निर्णय के समनरूप बिहार सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना वांछित है ।

भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त पत्र में भी विभिन्न विभागों से विमर्शोपरान्त तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस संबंध में पारित आदेश के आलोक में उक्त निर्णय लिया जाना उल्लिखित है ।


(9) उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी बिहार सरकार द्वारा भारत सरकार के द्वारा गठित वेतन आयोगों की अनुशंसा एवं सेवा शर्तों से संबंधित विषयों पर भी समनरूप निर्णय लिया जाता रहा है । अतः इस संबंध में यदि बिहार सरकार द्वारा भी उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा उक्त वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना से वापस ले लिया जायेगा, इससे समय एवं संसाधन के अपव्यय से बचा जा सकेगा ।

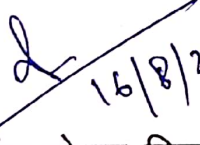
(8)

अतः पुनः अनुरोध है कि उक्त प्रासंगिक भारत सरकार के अधिसूचना एवं निर्णयों तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या -1/ पेन- 1001/2023-सा0प्र0-14593, दिनांक 01.08.2023 के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. संख्या - 10901/2006 मो0 क्यूमउद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार में दिनांक-03.08.2021 को पारित आदेश के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधानों के अधीन पुरानी पेंशन (OPS) योजना का लाभ दिए जाने के बिन्दु पर निर्णय लेने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोपरि ।

विश्वासभाजन,


(सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव


(शशांक शेखर सिन्हा)
अध्यक्ष

~~21/01/21~~ - II

~~21/01/21~~ - 1

1/3

No. 57/05/2021-P&PW(B)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, the 03rd March, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Coverage under Central Civil Services (Pension) Rules, in place of National Pension System, of those Central Government employees who were recruited against the posts/vacancies advertised /notified for recruitment, on or before 22.12.2003.

The undersigned is directed to say that consequent on introduction of National Pension System (NPS) vide Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003, all Government servants appointed on or after 01.01.2004 to the posts in the Central Government service (except armed forces) are mandatorily covered under the said scheme. The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and other connected rules were also amended vide Notification dated 30.12.2003 and, after the said amendment, those rules are not applicable to the Government servants appointed to Government service after 31.12.2003.

2. Subsequently, Department of Pension and Pensioners' Welfare in consultation with the Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of Hon'ble Courts, issued instructions vide OM No. 57/04/2019-P&PW(B) dated 17.02.2020 giving one time option to Central Government employees who were declared successful for recruitment in the results declared on or before 31.12.2003 against vacancies which occurred before 01.01.2004 and were covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, to be covered under the CCS(Pension) Rules, 1972 (now 2021). There was fixed time schedule for different activities under the aforesaid OM dated 17.02.2020.

3. Representations have been received in this Department from the Government servants appointed on or after 01.01.2004 requesting for extending the benefit of the pension scheme under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021) on the ground that their appointment was made against the posts/vacancies advertised/notified for recruitment prior to notification for National Pension System, referring to court judgments of various Hon'ble High Courts and Hon'ble Central Administrative Tribunals allowing such benefits to applicants.



4. The matter has been examined in consultation with the Department of Financial Services, Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of the Courts in this regard. It has now been decided that, in all cases where the Central Government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised/notified for recruitment/appointment, prior to the date of notification for National Pension System i.e. 22.12.2003 and is covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given a one-time option to be covered under the CCS(Pension) Rules, 1972 (now 2021). This option may be exercised by the concerned Government servants latest by 31.08.2023.

5. Those Government servants who are eligible to exercise option in accordance with para-4 above, but who do not exercise this option by the stipulated date, shall continue to be covered by the National Pension System.

6. The option once exercised shall be final.

7. The matter regarding coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), based on the option exercised by the Government servant, shall be placed before the Appointing Authority of the posts for which such option is being exercised for consideration, in accordance with these instructions. In case the Government servant fulfills the conditions for coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), in accordance with these instructions, necessary order in this regard shall be issued latest by 31st October, 2023. The NPS account of such Government servants shall, consequently, be closed w.e.f. 31st December, 2023.

8. The Government servants who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), shall be required to subscribe to the General Provident Fund (GPF). Regarding account of the corpus in the NPS account of the Government servant, Controller General of Accounts (CGA) has furnished the following clarification vide letter No. 1(7)(2)/2010/cia/TA III/390 dated 14.11.2019 & I.D. Note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308/450 dated 23.12.2022:

- i. **Adjustment of Employees' contribution in Accounts:** Amount may be credited to individual's GPF account and the account may be recasted permitting up-to-date interest (Authority-FR-16 & Rule 11 of GPF Rules).
- ii. **Adjustment of Government contribution under NPS in Accounts:** To be accounted for as (-) Dr. to object head 70 - Deduct Recoveries under Major Head 2071 - Pension and other Retirement benefit - Minor Head 911- Deduct Recoveries of over payment (GAR 35 and para 3.10 of List of Major and Minor Heads of Accounts).




iii. **Adjustment of increased value of subscription on account of appreciation of investments** - May be accounted for by crediting the amount to Govt. account under M.H. 0071- Contribution towards Pension and Other Retirements Benefits 800- Other Receipts (Note under the above Head in LMMIA)

9. All Ministries/Departments are requested to give wide publicity to these orders without fail. The cases of those Government servants who fulfill the conditions mentioned in this O.M. and who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021) may be settled by the administrative Ministries/Departments in accordance with these orders.

10. This issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure vide ID Note No. 1(7)/EV/2019 dated 05.12.2022 & 07.02.2023 and in consultation with Controller General of Accounts vide their I.D. Note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308/450 dated 23.12.2022.

11. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

12. Hindi version will follow.


03.03.2023

(Sanjiv Narain Mathur)
Additional Secretary to Government of India

To,

1. All Central Government Ministries / Departments.
 2. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
 3. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
 4. Ministry of Railways, Railway Board, for information, New Delhi.
 5. Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi.
 6. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
-
7. AD (OL) for Hindi version.
 8. NIC for uploading on Department's website.

3

No.25011/02/2021-AIS-II(Pension)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated 17/07/2023

To
The Chief Secretaries
All State Governments and UTs

Subject: Coverage under All India Services (Death Cum Retirement Benefits) Rules, 1958, in place of National Pension System, of those members of All India Services who were recruited against the posts/vacancies advertised/notified on or before 22.12.2003.

Sir/Madam,

Consequent on introduction of National Pension System (NPS) vide Ministry of Finance Notification No.5/7/2003-ECB&PR dated 22.12.2003, All India Services (Death-Cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 and All India Services (Provident Fund) Rules, 1955 were amended vide Notifications dated 07.02.2004 & 17.05.2004 respectively to mandate that the members of All India Services (AIS) appointed on or after 01.01.2004 will be covered under NPS, and that the benefits of the old Defined Benefit Pension Scheme and GPF will not be available to them.

2. Subsequently, on the basis of the judgments of various Hon'ble Courts and Hon'ble CATs allowing benefits of the old Defined Benefit Pension Scheme to Government servants appointed on or after 01.01.2004 against the posts/vacancies advertised for recruitment prior to the notification of NPS (i.e. 22.12.2003), representations have been received in this Department from similarly placed members of AIS requesting extension of benefit of pension scheme under AIS (DCRB) Rules, 1958.

3. The matter has been examined in consultation with the Department of Expenditure and it has been decided that **the AIS officers, who have been appointed against a post/vacancy which was advertised/notified for recruitment prior to the date of notification of NPS (i.e. 22.12.2003) and who are covered under NPS on joining Service on or after 01.01.2004, may be granted one-time option to be covered under the provisions of old pension scheme under AIS (DCRB) Rules, 1958.**

Therefore, members of AIS selected through Civil Services Examination, 2003, Civil Services Examination, 2004 and Indian Forest Service Examination, 2003 are eligible to be covered under these provisions.

(1/3)

4. Further, the members of Service, who prior to joining AIS were selected in a Central Government service which was covered under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021) or any other similar rules, are also eligible to be covered under the provisions of D/o P&PW O.M. dated 03.03.2023 and, hence, are eligible to be granted one-time option to be covered under the provisions of old pension scheme under AIS (DCRB) Rules, 1958.

It is clarified that the mobility from one service to another is subject to continuous service and technical resignation (as provided in this Department's OM No. 25011/6/2014-AIS(II) dated 04.11.2015).

5. The option exercised by the members of Service in accordance with these instructions shall be placed before the Government of the State on whose Cadre the member of Service is borne. If any clarification is required, a reference may be sent to the Department of Personnel and Training in case of members of Indian Administrative Service; to the Ministry of Home Affairs in case of members of Indian Police Service; and to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in case of members of Indian Forest Service.

6. This option may be exercised by the concerned members of Service **latest by 30th November, 2023**. The members of Service, who are eligible to exercise the option in accordance with these instructions but who do not exercise this option by the stipulated date, shall continue to be covered by NPS. The option once exercised shall be final.

7. In case the member of Service fulfills the conditions for coverage under AIS (DCRB) Rules, 1958 in accordance with these instructions, **necessary order in this regard shall be issued latest by 31st January, 2024.** The NPS account of such member of Service shall, consequently, be closed with effect from 31st March, 2024.

8. The members of Service who opt for old pension scheme under AIS (DCRB) Rules, 1958, shall be required to subscribe to the General Provident Fund (GPF). Accordingly, the Controller General of Accounts (Department of Expenditure) has clarified the following procedure for accounting of the corpus in the NPS account of the member of Service:-

a. **Adjustment of Employees' contribution** - Amount shall be credited to the individual's GPF account and the account shall be re-casted permitting up-to-date interest (FR 16 and Rule 9 of All India Services (Provident Fund) Rules, 1955).

However, for the period of service under Central government, employee contribution shall first be credited to 8658-Suspense Accounts, 8658.00.101-Pay and Accounts Office Suspense 'Transactions adjustable with Accounts officer (Name of the State Accountant General)' then the same shall be remitted to Accounts Office of concerned State Accountant General maintaining GPF account by relieving PAO Suspense.

(3/3)

b . **Adjustment of Government contribution** - Amount contributed towards NPS by the Central Government shall be credited to the account of the Central Government; and Amount contributed towards NPS by the State Government shall be credited to the account of the State Government.

The portion of the amount representing Government contribution shall be accounted for as (-) debit to object Head 70-deduct recoveries under Major Head 2071-Pension and Other retirement benefit-Minor Head-911 deduct recoveries of over payment - subhead -03- "Moneys remitted by PFRDA (AIS)" (GAR 35 and para 3.10 of list of Major and Minor Heads of Accounts).

c . **Adjustment of appreciation of investments** - The increased value of subscription on account of appreciation on investments shall be accounted for by crediting the amount to the Central Government or the concerned State Government account, as the case may be, in the proportion in which the adjustment of Government contribution is finalized. Appreciation of investment shall be accounted for by crediting the amount to Govt. Account under M.H. 0071-Contribution towards Pension and other Retirements Benefits 800-Other Receipts.

9. This issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure vide ID Note No.1(7)/E-V/2019 dated 04.07.2023 and with Controller General of Accounts vide UO No.TA-3-07001/6/2021-TA-III/cs-6776/236 dated 07.06.2023 and undated UO No.TA-3-07001/6/2021-TA-III/cs-6776/262.

Enclosed: As above.

Yours sincerely,

(Kuldeep Chaudhary)

Under Secretary to Government of India
Tel: 011-2309 4714

Copy to:

- i. Joint Secretary (Police-I), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi
- ii. Joint Secretary (UTS-I), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi
- iii. Joint Secretary (IFS), Ministry of Environments, Forest & Climate Change, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi
- iv. All Central Government Ministries/Departments
- v. Office of Controller General Of Accounts, Mahalekha Niyantarak Bhawan, Ministry of Finance, GPO Complex, Block E, Aviation Colony, INA Colony, Delhi-110023
- vi. Accountant General in the States and UTs

(Kuldeep Chaudhary)

Under Secretary to Government of India

पटना-15, दिनांक 13/07/2023

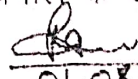
आदेश संख्या-1/पेन-1001/2023-सा0प्र0-1/कार्मिक लोक शिफायन और पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार नई दिल्ली के परिपत्र संख्या-25011/02/2021-AIS-III (पेंशन) दिनांक 13/07/2023 के निर्देशों के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन पी एस) के अधिसूचित होने की तिथि (22.12.2003) के पूर्व नियुक्ति हेतु विज्ञापित/अधिसूचित पद/रिक्ति के विरुद्ध 01.01.2004 या उसके बाद की तिथि को नियुक्ति के उपरान्त योगदान के समय निम्नांकित पदाधिकारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन पी एस) से आच्छादित सेवा को अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के प्रावधानों के अधीन पुरानी पेंशन योजना का आच्छादन प्रदान करते हुए उसके सभी अनुवर्ती लाभ दिए जाते हैं:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम	भा.प्र.से. में आवंटित बैच	सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित अधिसूचना की तिथि	केन्द्रीय सिविल सेवा / भा. प्र.से. में योगदान की तिथि	केन्द्रीय सिविल सेवा / भा. प्र.से. में योगदान की तिथि	वर्तमान पदस्थापन
1	श्रीमती पलका साहनी	2004	07.12.2002	-	06.09.2004	संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
2	श्री आर.लक्ष्मणन	2004	07.12.2002	-	06.09.2004	संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3	श्री अभय कुमार सिंह	2004	07.12.2002	-	06.09.2004	सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना
4	श्री (डॉ०) वीरेन्द्र प्रसाद यादव	2004	07.12.2002	-	06.09.2004	विशेष सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना
5	श्री मनीष कुमार	2005	29.11.2003	-	22.08.2005	आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा

6	श्री कुमार रवि	2005	07.12.2002	27.12.2004	22.08.2005	सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
7	श्री दिवेश सेहरा	2005	29.11.2003	-	22.08.2005	सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना
8	श्री कुलदीप नारायण	2005	29.11.2003	-	22.08.2005	संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
9	श्री बालामुरुगन .डी.	2005	29.11.2003	-	22.08.2005	संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
10	श्री संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी	2006	29.11.2003	05.12.2005	29.08.2006	सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
11	सुश्री रंजिता	2013	29.11.2003	22.08.2005	03.09.2012	श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना

2. सभी आलोच्य पदाधिकारियों को भविष्य निधि लेखा आवटित किए जाने हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा विधिवत् कार्रवाई की जाएगी। उक्त लेखा में राशि का संधारण भारत सरकार के परिपत्र संख्या-25011/02/2021-AIS-III (पेंशन) दिनांक 13.07.2023 के अनुसार किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


01.08.23
(रचना पाटिल)

सरकार के विशेष सचिव।

क.पू.ऊ.

Bihar Administrative Service Association

Shashank Shekhar Sinha
President

Mob. No.-9334118192



Sunil Kumar Tiwary

General Secretary

Mob. No.- 9431085120

Memo No 27

Date 12/04/2023

Vice President

Ajay Kumar

9835737317

Subodh Kumar

7979919465

Joint Secretary

Chandrashekhar Azad

8987044905

Vikash Kumar

7717770977

Treasurer

Shashi Shekhar

9334557086

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार सरकार, पटना

विषय:-भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi के Office Memorandum no.-57/05/2021-P&PW (B), Dated-03.03.2023 के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के 46 वीं एवं 47 वीं बैच के पदाधिकारियों को पुरानी पेशन योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या-1964, दिनांक 31.08.2005 के द्वारा आदेश निर्गत हुआ कि दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को नई पेशन योजना (NPS) से आच्छादित किया जायेगा (अनुलग्नक I)। इसी क्रम में दिनांक-01.09.2005 के बाद नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भी नई पेशन योजना (NPS) से आच्छादित किया गया है। नई पेशन योजना के संबंध में भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi के Office Memorandum no-57/05/2021-P&PW(B), Dated 03.03.2023 के द्वारा एक अधिसूचना निर्गत किया गया है कि जैसे सरकारी कर्मी जिनकी नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22.12.03 या उसके पूर्व निर्गत हो, लेकिन उनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार के अधीन 01.01.04 से लागू नई पेशन योजना (NPS) के बाद हुई हो, उनको भी पुरानी पेशन योजना (OPS) से लाभान्वित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके कंडिका 4 में उल्लिखित प्रावधान निम्नवत है :-

The matter has been examined in consultation with the Department of Financial Services, Department of Personnel &

o/c

Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of the Courts in this regard. It has now been decided the, in all cases where the Central Government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised/notified for recruitment/appointment, prior to the date of notification for National Pension System i.e 22.12.2003 and is covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given a one-time option to be covered under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021). This option may be exercised by the concerned Government servants latest by 31.08.2023.

(अनुलग्नक II)

अतः भारत सरकार से निर्गत उक्त पत्र के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) से लाभान्वित करने के निम्नलिखित आधार हैं :-

1. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों हेतु चिन्हित रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 03.02.2004 (दैनिक जागरण) (अनुलग्नक III) एवं दिनांक-05.11.2004 (Times of India) (अनुलग्नक IV) को किया गया था ।

2. इस क्रम में दिनांक 03.02.2004 के दैनिक जागरण समाचार पत्र में 46वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका-6 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री दिनांक-31.03.2004 के पूर्व की तथा दिनांक-14.12.2004 को हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण सहित अन्य समाचार पत्रों में 47वीं संयुक्त (प्रा0) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका-6 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री दिनांक-01.08.2001 के पहले की होनी चाहिए जिसे बाद में 31.12.2004 तक औपबंधिक रूप से कट-ऑफ डेट निर्धारित किया गया ।

3. उक्त विज्ञापनों के आधार पर दिनांक-18 जून, 2007 को 46वीं बैच के चयनित पदाधिकारियों की अधिसूचना बिहार गजट (अनुलग्नक- V) में प्रकाशित की गई तथा 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक-24.01.2009 (अनुलग्नक- VI) को प्रकाशित किया गया ।

4. उपरोक्त अनुलग्नक- III, 46वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका-1 में अधिकतम उम्र सीमा दिनांक-01.08.2000 तथा अनुलग्नक-IV, 47 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका-1 में अधिकतम उम्र की गणना दिनांक-01.08.2001 के आधार पर किया जाना स्पष्ट किया गया है ।

5. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि 46वीं एवं 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन, चयन की अधिसूचना तक कहीं भी नई पेंशन योजना से उक्त रिक्तियों को आच्छादित किया जाना स्पष्ट नहीं किया गया है अर्थात् उक्त दोनों 46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारीगण दिनांक-01.09.2005 के पहले के प्रचलित पेंशन नियमावली के आलोक में ही विज्ञापन प्रकाशित की गयी है ।


6. इस संबंध में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा अपने पत्र संख्या-21, दिनांक-13.07.2021 द्वारा भी प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार को C.W.J.C. संख्या-10901/2006 मो० बयूमउद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार (अनुलग्नक-VII) वाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-03.08.2011 को पारित आदेश- **It is infact this aspect of matter which would clinch the issue in favour of the petitioners in as much as it is well settles by now that old vacancies have to be Government by the old rules coming into force after beginning of process of selection as per old rules can not be made applicable** के आलोक में- "नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के पूर्व नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त किए गए पदाधिकारियों/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाय", अनुरोध किया गया था (अनुलग्नक- VIII)।

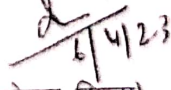
7. इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि C.W.J.C. संख्या-2312/2022 बिहार प्रशासनिक सेवा संघ बनाम बिहार सरकार वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया है जो प्रक्रियाधीन है (अनुलग्नक- IX) भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त पत्र में भी विभिन्न विभागों से विमर्शोपरान्त तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस संबंध में पारित आदेश के आलोक में उक्त निर्णय लिया जाना उल्लिखित है।

अतएव इस संबंध में यदि बिहार सरकार द्वारा भी उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो बिहार प्रशासनिक सेवा संघ सरकार के इस कदम का स्वागत करेगा। साथ ही इससे उभय पक्षों के समय एवं संसाधन के अपव्यय से भी बचा जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. संख्या-10901/2006 मो० बयूमउद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार में दिनांक-03.08.2021 को पारित आदेश एवं भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi के Office Memorandum no.-57/05/2021-P&PW (B), Dated-03.03.2023 के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधानों के अधीन पुरानी पेंशन (OPS) योजना का लाभ दिए जाने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोपरि ।


(सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव,

विश्वासभाजन

(शशांक शेखर सिन्हा)
अध्यक्ष,

परिशिष्ट - I

पारितोषिक
I

संघिका संख्या- वि०(27)१०१०-53/०4 - 1764

बिहार सरकार
वित्त विभाग

पटना, दिनांक- 31.8.2005

संकेत

विषय- दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए नयी अंशदायी पेंशन योजना ।

1. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर, लिये गये निर्णयों के आलोक में सम्प्रति राज्यकर्मियों को केन्द्र सरकार के कर्मियों के अनुरूप वेतनमान, भत्ता, सेवानिवृत्ति की आयु आदि की सुविधायें अनुमान्य है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय प्रभाग, नई दिल्ली के पत्रांक-05/07/2003 ई०सी०वी० नं० 22.12.2003 द्वारा भारत सरकार के अधीन दिनांक-01.01.2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए वर्तमान में प्रचलित पेंशन योजना के स्थान पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है । संसद द्वारा भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के लिए प्रख्यापित अंशदायी पेंशन योजना के सदृश्य राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित विचारोपरत दिनांक-01.09.2005 के प्रभाव से अंशदायी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसका नाम "बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना-2005" होगा ।

3. इस संकेत में निहित प्रावधान जैसे सरकारी सेवकों के मामले में लागू होगी योजनाकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन दिनांक-01.09.2005 को या उसके बाद हुई हो, परन्तु उक्त प्रावधान संविदा, राज्य सरकारों एवं स्वायत्त संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर आय कर्मियों, दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों तथा प्रतिनियुक्त कर्मियों पर लागू नहीं होगी ।

4. दिनांक-01.09.2005 या उसके बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्त कर्मियों में वार्षिक वेतन में से मूल वेतन-अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के योग की 10 (दस) प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में कटौती की जायेगी तथा उतनी ही राशि नियोजता अर्थात् राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दी जायेगी ।

5. योजनान्तर्गत संबंधित कर्मियों के अंशदान की कटौती उनके योगदान के अगले माह से प्रारम्भ होगी अर्थात् यदि सितम्बर, 2005 में कटौती में योगदान किया हो तो अंशदान की कटौती अक्टूबर, 2005 में प्रारम्भ होगी ।

6. योजना प्रवृत्त होने की तिथि 01.09.2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के मामलों में वर्तमान में लागू सामान्य भविष्य निधि तथा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात् सामान्य भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की कटौती नहीं की जायेगी ।

7. योजनान्तर्गत अंशदान की कटौती तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये अंशदान संबंधी लेखा का प्रारम्भ तत्पश्चात् भविष्यनिधि निदेशालय/कार्यालय द्वारा किया जायेगा तथा भविष्य निधि निदेशालय/कार्यालय द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना के अधीन अंशदान की कटौती के लिए एक लेखा संख्या आवंटित की जायेगी ।

8. नई पेंशन योजनान्तर्गत संबंधित कर्मों की सेवानिवृत्ति के समय सेवाकाल में संचित निधि की (अनुमान्य) प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से वार्षिकी खरीदने (आई० आर० डी० ए० नियमित जीवन बीमा कर्मियों से) के लिए कटौती कर ली जायेगी जिससे सरकारी कर्मचारी तथा उस पर आश्रित उसके माता-पिता तथा पत्नी-पत्नी के जीवन काल हेतु पेंशन की व्यवस्था की जायेगी तथा शेष 60(साठ) प्रतिशत राशि एक

संशोधन सरकारी सेवक को भुगतान कर दी जायेगी।

9. इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अलग से विस्तृत आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

10. जब तक पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण गठित नहीं हो जाना है, तबतक कर्मियों तथा अशरतों की राशि लोक लेखा में रखी जायेगी तथा इस पर सामान्य भविष्य निधि की दर से व्यय देय होगा।

11. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय आदि जहाँ राज्य सरकार के कर्मियों को भांति पेंशन की सुविधा उपलब्ध है को इस नई अंशदायी पेंशन योजना को अनिवार्य रूप से लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाये

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

~~पी० एन० नारायणन,~~
वित्त आयुक्त। 31/8/5

आदेश- 19(27) 4/10/53-53/04-1964 पटना, दिनांक- 31.8.2005
प्रतिनिधि- महालेखाकार, बिहार, धीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~पी० एन० नारायणन,~~
वित्त आयुक्त। 31/8/5

आदेश- 19(27) 4/10/53-53/04-1964 पटना, दिनांक- 31.8.2005
प्रतिनिधि- सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय आरक्षी महालेखाकार/निबंधक उच्च न्यायालय पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/सभी महालेखा/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समादेश्या को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~मंगल चौधरी,~~
उप सचिव। 31/8/05

आदेश- 19(27) 4/10/53-53/04-1964 पटना, दिनांक- 31.8.2005
प्रतिनिधि- संयुक्त आयुक्त लेखा प्रशासन, पंत भवन, पटना/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/सभी क्षेत्राधिकार/उप क्षेत्राधिकार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~मंगल चौधरी,~~
उप सचिव। 31/8/05

आदेश- 19(27) 4/10/53-53/04-1964 पटना, दिनांक- 31.8.2005
प्रतिनिधि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस, मुलजानबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~मंगल चौधरी,~~
उप सचिव। 31/8/05

अनुरोध है कि उक्त संकल्प की 1000 प्रति मुद्रित कर वित्त विभाग (पेंशन कोषांग) को प्रेषित कर उपलब्ध कराया जाए।

~~मंगल चौधरी,~~
उप सचिव। 31/8/05

(12)

बिहार लोक सेवा आयोग

15 नवम्बर 2004 को जारी प्राज्ञ (अतिरिक्त) पटना - 800001

47वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा

(17)

विहित क्रमवारी में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्नों के उत्तर देने में कुल 120 मिनट दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर देने में कुल 120 मिनट दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर देने में कुल 120 मिनट दिए गए हैं।

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
प्रारंभिक (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र
(अतिरिक्त) पटना का पोस्टाफिस
पटना - 800001

Times of India - 05-11-2004

Certified
Section Officer
Bihar Public Service Commission
PATNA

अनुक्रमिका - 8
 अनुक्रमिका - V - Annexure - 2 Series

13
 1/2

विभाग सं. 103 210-40



बिहार राजपत्र

असाधारण अंक
 बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अक्टूबर 1971 (शुक्र)
 भा.सं. संख्या 31 मूल 2007
 पहला अंक साप्ताहिक सुधार विभाग

13 मूल 2007

श्री 17 510 1032/2007/40 2010-विभा सं. 103 210-40-असाधारण अंक की अर्थ प्रवृत्ति अधिनियम तैयार की असाधारण अंक प्रकाशित किया है। (असाधारण अंक) अधिनियम अधिनियम की असाधारण अंक प्रकाशित किया है।
 2. असाधारण अंक प्रकाशित करने के लिए असाधारण अंक प्रकाशित किया है।

क्र. सं.	नाम	पद	व्यवस्थापक	आवृत्ति	आवृत्ति
1	श्री 103 210-40	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक
2	श्री 103 210-40	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक
3	श्री 103 210-40	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक
4	श्री 103 210-40	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक
5	श्री 103 210-40	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक
6	श्री 103 210-40	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक
7	श्री 103 210-40	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक
8	श्री 103 210-40	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक
9	श्री 103 210-40	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक
10	श्री 103 210-40	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक
11	श्री 103 210-40	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक
12	श्री 103 210-40	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक
13	श्री 103 210-40	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक
14	श्री 103 210-40	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक
15	श्री 103 210-40	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक	असाधारण अंक

22

14

बिहार राज्य (संरचना), 27 जून 2007

क्र.सं.	नाम	संयुक्त क्षेत्र का नाम	भारतीय विधि	अंतर्गत स्थानों का नाम
13	श्रीमती विद्यादेवी	36	सामान्य	श्रीगंगा
16	श्री सुधीर कुमार	27	सामान्य	सारन (उपखंड)
17	श्री सुधीर कुमार	29	सामान्य	साधुसराय
18	श्री परमानंद कुमार	30	सामान्य	गया
19	श्री मोठे आशोक कुमार	31	सामान्य	गोपालगंज
20	श्री प्रभात कुमार	32	सामान्य	सोनभद्र
21	श्री निवेक	35	पिछड़ी जाति	मधेपुरा
22	श्री प्रियंका देवी	36	अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति	परिव्रज जिला
23	श्री अमरेंद्र कुमार	40	पिछड़ी जाति	मुजफ्फरपुर
24	श्री मोठे नरेश कुमार	43	अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति	सोनभद्र
25	श्री मनोज कुमार	45	पिछड़ी जाति	शिवहर
26	श्री विनायक कुमार	46	पिछड़ी जाति	पूर्वी चम्पारण
27	श्री मोठे राहुल कुमार	47	अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति	बेगूसराय
28	श्री मोठे सुधीर कुमार	49	अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति	दरभंगा
29	श्री राजेश कुमार	51	पिछड़ी जाति	पटना
30	श्री प्रभात कुमार	53	अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति	मधुबनी
31	श्री सुधीर कुमार	56	पिछड़ी जाति महिला	सहरसा
32	श्री अमरेंद्र कुमार अरवि विभागी	57	अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति	समस्तीपुर
33	श्री मोठे सुधीर कुमार	61	अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति	सुपौल
34	श्री नरेश कुमार	62	अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति	बेगूसराय
35	श्री अमरेंद्र कुमार	63	अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति	सुपौल
36	श्री सुधीर कुमार	70	अनुसूचित जाति	मधेपुरा
37	श्री विद्यादेवी अरवि	137	अनुसूचित जाति	सुपौल
38	श्री राजेश कुमार	169	अनुसूचित जाति	अररिया
39	श्री नील कुमार	187	अनुसूचित जाति	किसानगंज
40	श्री मनोज कुमार	197	अनुसूचित जाति	कटिहार
41	श्री सुधीर कुमार अरवि	199	अनुसूचित जाति	मुजफ्फरपुर
42	श्री सुधीर कुमार	206	अनुसूचित जाति	भागलपुर

उपरोक्त अधिसूचना किन्तु अल्पसंख्यक जातियों के अधीन की जाती है:-

(क) रजिस्ट्रार/अल्पसंख्यक जातियों के प्रति एवं पूर्ववर्त सत्यापन संबंधी कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनका सेवा नियुक्ति प्रभाव ही विरत हो जाएगा।

(ख) संपूर्ण प्रमाण पत्र/संश्लेषित प्रमाणिका/अल्पसंख्यक जातियों के सत्यापन पत्रों को सत्यापित में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो सत्यापन पत्र/संश्लेषित प्रमाणिका/अल्पसंख्यक जातियों के सत्यापन पत्रों को जमा रखा जाएगा एवं आवश्यक विधियां काटाई की जाएगी।

(ग) अल्पसंख्यक जातियों के सत्यापन पत्रों पर पर्यवेक्षण उप-संगठनों अपने-अपने क्षेत्रों में सत्यापन कार्य करते-करते अल्पसंख्यक जातियों के सत्यापन पत्रों पर प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अल्पसंख्यक जातियों के सत्यापन पत्रों को जमा रखा जाएगा एवं आवश्यक विधियां काटाई की जाएगी।

(घ) अल्पसंख्यक जातियों के सत्यापन पत्रों पर पर्यवेक्षण उप-संगठनों अपने-अपने क्षेत्रों में सत्यापन कार्य करते-करते अल्पसंख्यक जातियों के सत्यापन पत्रों पर प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अल्पसंख्यक जातियों के सत्यापन पत्रों को जमा रखा जाएगा एवं आवश्यक विधियां काटाई की जाएगी।

(ङ) अल्पसंख्यक जातियों के सत्यापन पत्रों पर पर्यवेक्षण उप-संगठनों अपने-अपने क्षेत्रों में सत्यापन कार्य करते-करते अल्पसंख्यक जातियों के सत्यापन पत्रों पर प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अल्पसंख्यक जातियों के सत्यापन पत्रों को जमा रखा जाएगा एवं आवश्यक विधियां काटाई की जाएगी।

बिहार राज्य (संरचना) अधिसूचना, 27 जून 2007
 आचार्य सुभाष चंद्र बोस
 राज्यपाल

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (पैली रोड), पटना - 800001

47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर एक

47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अंतर्गत साक्षात्कार हेतु घणित कुल 224 उम्मीदवारों की मॉडिक परीक्षा/साक्षात्कार रिजल्ट 12.01.2009 से 14.01.2009 की अवधि में सापेक्ष हुआ। उक्त मॉडिक परीक्षा/साक्षात्कार में चार उम्मीदवार, अनुक्रमांक 129040, रामु कुमार सिंह अनुक्रमांक 129040, हरिचंद्र नाथ, अनुक्रमांक 130612, संजय कुमार एवं अनुक्रमांक 149929, संजय नारती ने भाग नहीं लिया। शेष 220 उम्मीदवारों की उनकी (मुख्य) लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांकों की जोड़ के अनुसार तीनों की गयी संयुक्त क्रमिक मेधा सूची में अर्थात् राज्य संघर्ष/सेवाओं के लिए उनके द्वारा इंगित अधिमान-क्रम को प्रथम देने हुए घणित सेवा के लिए उनकी सुयोग्यता तथा आरक्षित/रिजर्व पर-उपलब्धता के अनुसार विभाजित उम्मीदवारों को इंगित राज्य संघर्ष/सेवा में नियुक्ति हेतु सफल घोषित किया जाता है-

क्रम सं.	अनुक्रमांक	नाम	श्रेणी क्रमांक	आवंटित आरक्षण श्रेणी रिजल्ट
(1) बिहार प्रशासनिक सेवा:				
1.	134330	हरिचंद्र प्रसाद कुमार	6	साधारण
2.	107067	राजेश्वरी पाण्डेय	6	साधारण
3.	110601	प्रमोद प्रसाद	7	साधारण
4.	124075	शैलज कुमार दास	8	साधारण
5.	142530	रामु नाथ	9	साधारण
6.	102574	किरीट कुमार	10	साधारण
7.	128331	संजय कुमार	11	साधारण
8.	111118	दुर्गा कुमार	12	साधारण
9.	102012	पद्मेश्वर झा	13	साधारण
10.	115309	राजेश कुमार	14	साधारण
11.	103032	गिरिश कुमार	15	साधारण
12.	150349	अमित कुमार तिवारी	16	साधारण
13.	107079	देवेंद्र प्रसाद साहू	17	साधारण
14.	147319	हरि रंजित	18	साधारण
15.	102338	मधु कौशल	20	साधारण
16.	100254	रविंद्र प्रसाद दिवाकर	21	साधारण
17.	104950	नील सिंह	22	साधारण
18.	151005	गोपाल प्रसाद सिंह	23	साधारण
19.	103384	अशोक कुमार	26	विद्यार्थी वर्ग
20.	100604	अशोक कुमार गुप्ता	26	विद्यार्थी वर्ग
21.	130314	सुरेश कुमार अलबेला	29	विद्यार्थी वर्ग
22.	102363	संजय कुमार सिंह	33	विद्यार्थी वर्ग
23.	155008	अशोक कुमार गुप्त	35	अवकाश विद्यार्थी वर्ग
24.	106114	अनु कुमार	43	अवकाश विद्यार्थी वर्ग
25.	130441	प्रदीप मिश्रा	48	विद्यार्थी वर्ग की महिला
26.	112025	सुर प्रकाश	52	अवकाश विद्यार्थी वर्ग
27.	116220	राज्य अंतर्गत	64	अवकाश विद्यार्थी वर्ग
28.	132587	राज कुमार	65	विद्यार्थी वर्ग (विद्यार्थी वर्ग)
29.	120076	अशोक कुमार जसारी	74	अवकाश विद्यार्थी वर्ग
30.	140100	सुरेश कुमार	78	अवकाश विद्यार्थी वर्ग
31.	122304	हरेंद्र राय	104	अनुसूचित जाति
32.	112104	कुमार मनोज	128	अनुसूचित जाति
33.	127912	अशोक प्रकाश	153	अनुसूचित जाति
34.	126401	मिनाक्षी अशोक	165	अनुसूचित जाति
35.	126025	अशोक कुमार	168	अनुसूचित जाति
36.	156431	नवीन कुमार	171	अनुसूचित जाति
(2) बिहार शास्त्री सेवा:				
37.	112655	रंजित कुमार	1	साधारण
38.	113777	अशोक कुमार झा	2	साधारण
39.	153171	सुरेश कुमार सिंह प्रभाकर	3	साधारण
40.	126225	रम रंजन हरगढ़	4	साधारण
41.	126265	मनोज कुमार	56	अनुसूचित जाति
(3) अधिमान-क्रम अधिकारी:				
42.	102275	अशोक प्रसाद सिंह	24	साधारण
43.	174878	सुरेश कुमार	25	साधारण
44.	122821	अशोक कुमार प्रसाद	27	साधारण
45.	154431	रंजित कुमार	50	अवकाश विद्यार्थी वर्ग
46.	143000	संजय कुमार	185	अनुसूचित जाति

क्रम सं.	अनुक्रमांक	नाम	श्रेणी क्रमांक	आवंटित आरक्षण श्रेणी रिजल्ट
(4) शेष विद्यार्थी:				
47.	102259	राजेश कुमार सिंह	30	साधारण
48.	121836	अशोक कुमार सिंह	32	साधारण
49.	100061	प्रदीप कुमार	39	विद्यार्थी वर्ग
50.	184957	संजय कुमार	44	विद्यार्थी वर्ग
51.	106170	मनीष कुमार	80	अवकाश विद्यार्थी वर्ग
52.	112074	सुरेश कुमार	172	अनुसूचित जाति
(5) बिहार अर्थशास्त्री पदाधिकारी:				
53.	101014	सुरेश कुमार झा	31	साधारण
54.	130003	अशोक कुमार सिंह	34	साधारण
55.	112420	सुरेश कुमार	36	साधारण
56.	113120	सुरेश कुमार	45	साधारण
57.	118492	सुरेश कुमार	47	साधारण
58.	135091	विश्वनाथ रंजित	193	अनुसूचित जाति
59.	106714	अशोक कुमार	194	अनुसूचित जाति
(6) बिहार जमींदार:				
60.	127127	सुरेश कुमार	37	साधारण
61.	142208	विश्वनाथ कुमार	41	साधारण
62.	100688	अशोक कुमार प्रभाकर	42	साधारण
63.	109571	सुरेश कुमार झा	49	साधारण
64.	123289	विश्वनाथ कुमार	51	साधारण
65.	149004	मनीष कुमार	53	साधारण
66.	149150	सुरेश कुमार प्रभाकर	54	विद्यार्थी वर्ग
67.	164173	सुरेश कुमार	91	अवकाश विद्यार्थी वर्ग
68.	103416	मनीष तन्त	116	अवकाश विद्यार्थी वर्ग
69.	104997	सुरेश कुमार	150	अनुसूचित जाति
70.	102802	अशोक कुमार	195	अनुसूचित जाति
(7) सहायक विद्यार्थी, अध्यापक शक्तिवर्धन:				
71.	100733	सुरेश कुमार सिंह	38	साधारण
72.	171217	सुरेश कुमार	42	साधारण
73.	120999	अशोक प्रसाद	60	विद्यार्थी वर्ग
74.	103208	मनीष कुमार	69	अवकाश विद्यार्थी वर्ग
75.	127384	सुरेश कुमार	96	अवकाश विद्यार्थी वर्ग
76.	112272	मनीष कुमार	99	अवकाश विद्यार्थी वर्ग
77.	145036	सुरेश कुमार	107	विद्यार्थी वर्ग की महिला
78.	151078	अशोक कुमार	120	अवकाश विद्यार्थी वर्ग
79.	149469	अशोक कुमार	121	अवकाश विद्यार्थी वर्ग
80.	149700	सुरेश कुमार	131	विद्यार्थी वर्ग की महिला
(8) सुबका एवं धारणकर्ता पदाधिकारी:				
81.	156658	सुरेश कुमार	55	साधारण
82.	111876	अशोक कुमार	57	साधारण
83.	111982	अशोक कुमार	58	साधारण
84.	130748	सुरेश कुमार सिंह	59	साधारण
85.	117812	विश्वनाथ कुमार	61	साधारण
86.	106788	अशोक कुमार	69	विद्यार्थी वर्ग
87.	125456	सुरेश कुमार दिवाकर	182	अनुसूचित जाति

- उपरोक्त 220 उम्मीदवारों में से अनुक्रमांक 111501, नीलम कुमार (मेधा क्रमांक-19) एवं अनुक्रमांक 111822, शशि शंकर (मेधा क्रमांक-40) द्वारा सेवाओं के लिए दिये गये आधिकारिक अधिमान-क्रम के अर्थात् उनके उक्त मेधा-क्रमों तक तदनुसार रिजल्ट शेष नहीं रही, जिसे कारण उनकी नियुक्ति की अनुमति नहीं की जा सकती है; उक्त दो उम्मीदवारों ने उक्त सभी अवकाशों/पदों के लिए अपना अधिमान-क्रम अंकित नहीं किया है।
- परीक्षाफल के मुद्रण की किसी वृद्धि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।
- उपरोक्त परीक्षाफल आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> पर देखा जा सकता है।
- उपरोक्त परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों के लक्षात्कृत दिनांक 30.01.2009 से आयोग के उक्त वेबसाइट पर प्रकाशित रहेंगे एवं तदनुसार ही इसी आणनलॉक किया जा सकता है।

दिनांक: 24 जनवरी, 2009

Certified
 Section Officer
 Bihar Public Service Commission
 PATNA
 24/1/09
 उप सचिव-सहा-परीक्षा नियंत्रक,
 बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Columns, Newwa Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2001)

Website: basobihar.com, E-mail id: infobaso1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President

Mob. No.- 9334118192



Anil Kumar
General Secretary

Mob. No.- 9431409463

18

Memo No 21

Date 13.07.2021

ice President
d. Moeczuddin
9304951290

Ajay Kumar
9835737317

oint Secretary
ubodh Kumar
7979919465

opai Sharan
8210342042

Treasurer
l Kumar Tiwary
9431085120

int Treasurer
Mona Jha
9430881025

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

विषय:-

46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मुहैया कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

- (1) CWJC No-10901/2006 मो0 कसुमुदीन अंसारी बनाम बिहार सरकार वाद में दिनांक-03.08.2011 को पारित आदेश।
- (2) अघोहस्ताक्षरी का पत्रांक 09 दिनांक 15.01.2020 (छायाप्रति संलग्न)

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं एवं वर्तमान में बिहार सरकार के अधीन दिनांक-01.09.2005 के बाद लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित है जबकि 47वीं बैच के पदाधिकारियों को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधान अर्थात् पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिये जिसके निम्नलिखित आधार हैं:

2. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों हेतु चिन्हित रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन का प्रकाशन (छायाप्रति संलग्न) 05.11.2004 को किया गया था। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 14.12.2004 निर्धारित की गयी थी।

3. इस क्रम में दिनांक-14.12.2004 को हिन्दुस्तान दैनिक जागरण सहित अन्य समाचार पत्रों में विज्ञापन (छायाप्रति संलग्न) प्रकाशित किया गया, जिसमें उल्लिखित है कि 47वीं संयुक्त (श्री०) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के क्रम संख्या-8 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को परिभाषित करते हुए आवेदन जमा करने की तिथि को दिनांक-31.12.2004 तक बढ़ाया गया था।

h

4. उक्त विज्ञापन के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक-24.04.2005 को 47वीं संयुक्त (प्रा०) प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गयी तथा इसका परीक्षा फल (छायाप्रति संलग्न) बि.लो.से. आयोग द्वारा 16.12.2008 को घोषित किया गया।

5. 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अन्तर्गत साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा 12.01.2009 से 14.01.2009 तक आयोजित की गयी एवं अंतिम परिणाम (छायाप्रति संलग्न) 24.01.2009 को घोषित किया गया।

अतः उक्त साक्ष्य के अनुसार निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते हैं;

- (क) 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन वर्ष 2001 के आधार मानकर की गयी है।
- (ख) 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता हेतु प्रारम्भिक परीक्षा 24.04.2005 को आयोजित की गयी है।
- (ग) 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा हेतु अध्यायना मुख्य सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक 430 दिनांक 06.05.2005 के आलोक में की गयी है।

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि 47वीं संयुक्त बिहार प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के पदों की रिक्तियाँ नई पेंशन योजना अर्थात् 01.09.2005 के पहले लागू नियमावली के आलोक में की गयी है। इसी प्रकार का समदृश्य मामला 46वीं बैच के पदाधिकारी का भी है।

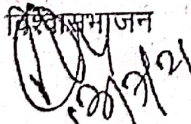
7. इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC सं०-10901/2006 के कयामुद्दीन अंसारी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में दिनांक 03.08.2011 को निम्नलिखित आदेश (छायाप्रति संलग्न) पारित है;


"It is infact this aspect of matter which would clinch the issue in favour of the petitioners in as much as it is well settled by now that old vacancies have to be governed by the old rules and the new rules coming into force after beginning of process of selection as per old rules can not be made applicable."

8. उक्त न्याय निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के पूर्व नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त किये गए पदाधिकारियों/कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाय।

9. अतः अनुरोध है कि उक्त न्यायादेश के आलोक में वित्त विभाग, बिहार सरकार को संकल्प सं० 1964 दिनांक 31.08.2005 की कड़िका 3 एवं कड़िका 6 में उल्लिखित प्रावधानों को धिल एवं क्षांत करते हुए 01.09.2005 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के लिए उच्चतरीय निर्णय लेने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-यथोपरि।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार)
महासचिव

विश्वासभाजन

(शशांक शंखर शिन्हा)
अध्यक्ष

31/8/11 - 10

31/8/11 - VIII

20
17

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
CIVIL WRIT JURISDICTION CASE No.10901 of 2006

1. Md.Kayumuddin Ansari, son of Shri Rahmat Ali Ansari, resident of Latif Market, Chokhandi Road, P.S. Sasaram, Sasaram
2. Krishna Kumari, D/o Shri Ramji Prasad Gupta, resident of village Sikarhgarh Tola (L.C.T. Ghat Road), near Mishra Medical Hall, P.O. + P.S. Kahalgaon, District Bhagalpur
3. Arun Kumar, son of Shri Parasnath Prasad, resident of Khajpura Ambedkar Path, P.O. B.V.College, P.S. Shastrinagar, Bailey Road, Patna-800014
4. Soena Kumari, D/o Shri Ajeet Kumar Yadav, resident of village + P.O. Lafa, P.S. Nawgachhiya, District Bhagalpur
5. Shashibhusan Kumar Sinha, son of Shri Janardan Prasad, resident of village Manara, P.S. Noorsarai, District Nalanda
6. Kiran Kumari, D/o Shri Jagdish Prasad, resident of village Bishnupur, P.O. Ranigar, P.S. Noorsarai, District Nalanda
7. Satish Kumar, son of Shri Jaleshwar Prasad Singh, resident of Health Institute Road, Beur, P.S. Gardaniabagh, Anisabad, District Patna-800002
8. Surendra Ram, son of late Ramdeni Ram, resident of village Mataya, P.O. P.S. Madhopur Ram, District Vaishali
9. Jitendra Kumar Sinha, son of Shri Ramprit Prasad, resident of village Katar, P.S. Atari, District Gaya

WEB
NOT OFF

Petitioners

Versus

1. The State Of Bihar through the Chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna
2. The Commissioner, Finance, Govt. of Bihar, Patna
3. The Commissioner cum Secretary, Health Services, Department of Health, Govt. of Bihar, Patna
4. The Joint Commissioner, Accounts Administration, Department of Finance, Contributory Provident Fund, Bihar, Patna
5. The Additional Secretary, Health and Family Welfare, Department, Vikash Bhawan, Patna
6. The State Drugs Controller, Directorate Health Services, Vikash Bhawan, Patna
7. The Bihar Public Service Commission, Bihar, patna, through its Secretary

Respondents

For the petitioners : Mr. Mithilesh Kumar Rai, Adv.
For the State : Mr. Bijay Kumar Pandey, A.C. to G.P.20
For the BPSC : Mr. Sanjay Pandey, Adv.

5. 3.8.2011

Having heard counsel for the parties as with regard

to the following relief:

"That this is an application for issuance of a writ in the nature of mandamus directing and commanding

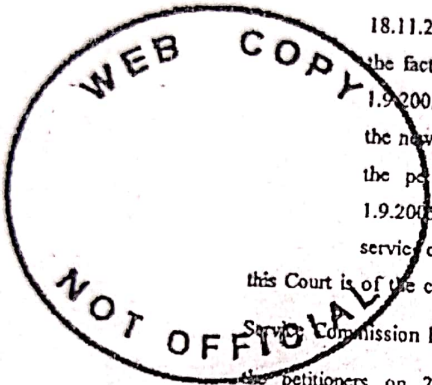
2/2

21

the respondent authorities not to give effect to letter no. 690 dated 3.3.2006, issued under the signature of the Joint Commissioner, Accounts Administration, Department of Finance, so far as it relates to the petitioners, which is said to have been pursuant to Gazette notification bearing No. 614 dated 18.11.2005, whereby and whereunder it speaks of the fact that the persons having been appointed on 1.9.2005 or thereafter, shall have to be a member of the newly contributory fund scheme, as also to treat the petitioner to have been appointed prior to 1.9.2005 for the purposes of application of the service condition in regard to pension."

this Court is of the considered opinion that as the Bihar Public Service Commission had ultimately recommended the names of the petitioners on 25.6.2004 in continuation to the earlier recommendation of 41 candidates vide its letter No. 39 dated 12.5.2003 by making it clear that the name of the petitioners shall be placed below the 40th candidate and above 41st candidate, there should have been no difficulty for the Government to allow the benefit of old pension scheme which was prevalent at the time of appointment of the 41st candidate.

The issue in fact becomes very simple if it is taken into account that by one advertisement No. 2 of 2000 the post of Drug Inspector were advertised but when the result of the same was published in the year 2001 the petitioners were shown to have been unsuccessful in the written test, whereas the Commission had recommended the name of the other 41 persons in the year 2003 after conducting interview and preparing selection list. The



3/7

92

petitioners and the similarly situated 7 persons alike the petitioners thereafter had assailed the result and recommendation of the Commission on a ground that they were illegally edged out without following the Government's own scheme and policy as with regard to lowering qualifying mark in the written test for the backward categories. This Court in its judgment dated 16.5.2002 in L.P.A.No. 1223 of 1999 and its analogous cases infact had upheld such claim and had directed the Commission to re-determine the merit list on the basis of qualifying marks prescribed under the statutory Rules. The Commission thereafter had made such exercise and sent its recommendation on 25.6.2004 wherein the name of 11 persons including the petitioners were recommended and it was clarified that their place of seniority will be below Sl.No. 40 and above Sl.No. 41 of the earlier list dated 12th May, 2003. Consequently such recommendation of the petitioners had not only been accepted by the Government but an offer of appointment was also issued to them on 11.8.2005 communicating that the Government had already decided them to appoint on the post of Drug Inspector and as such they should give their option of three districts for their respective place of posting. While all these things had already happened, the Government had taken a decision that from 1.9.2005 any person appointed in the Government service will not be entitled to the existing policy of pension being paid to them under the Bihar Pension Rules and they would be governed by a new contributory pension scheme framed by the government. Eventually when the petitioners were

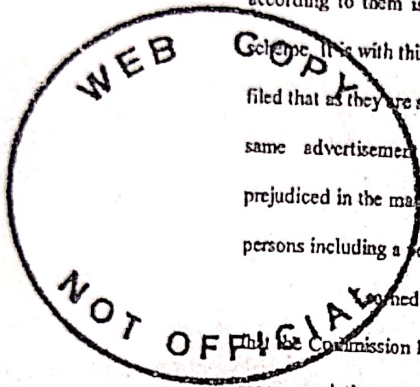
WEB COPY
NOT OFFICIAL

4/7

23

also appointed by a notification dated 28.11.2005 they were also deprived of the benefit of pension under old policy and scheme governed by Bihar Pension Rules and they were also coerced to accept the new policy of Contributory Pension Scheme which according to them is less beneficial in comparison to the earlier scheme. It is with this grievance that this writ application has been filed that as they are senior to the persons appointed on the basis of same advertisement and selection process they cannot be prejudiced in the matter of service condition as was given to other persons including a person below them in the merit list.

The learned counsel for the Commission has clarified that the Commission had gone into this exercise and had made its recommendation very clear that the place of the petitioners as per roster and reservation in view of the direction given by this Court in the judgment dated 16.5.2002 in L.P.A. No. 1823 of 1999, would be below SI.No.40 of the original list and above 41 of the same list. In fact the Commission has itself placed the revised recommendation dated 25.6.2004 and Mr. Pandey, appearing on behalf of the Commission, has also very fairly produced even the earlier recommendation 12.5.2003, which has been kept on the records of this case. From the simultaneous reading of the two recommendations of the Commission dated 12th May, 2003 and 25.6.2003 it would become absolutely clear that the petitioners will be deemed to be appointee of the same transaction and barring the benefit of payment of salary for the period they had not worked on account of denial of their appointment they were entitled for all



57

57

other benefits including seniority to which were extended to other 41 Drug Inspectors appointed earlier - in view of the recommendation of Commission in its letter dated 12.5.2003.

In that view of the matter, this Court would find it difficult to accept the submission of the learned counsel for the State who has given only one explanation by way of justification of the Government decision that the petitioners being appointee after 1.9.2005 were to be governed by the new contributory pension scheme. Such submission of learned counsel for the State is based on an arithmetical calculation that since the appointment letter of the petitioners was issued after cutoff date of 1.9.2005 they will be automatically deprived from availing the earlier benefit of pension under Bihar Pension Rules which was given to the appointees of the year 2003. This Court however would fail to understand the logic of such submission, inasmuch as when the petitioners were subjected to same selection process in terms of the same advertisement and ultimately their case was recommended by the Commission in continuation of the same merit list by placing them above a person who was originally recommended and appointed, it would be difficult to accept such justification given by the State Government that the petitioners still will be deprived of the benefit of the old pension scheme because they were appointed after 1.9.2005. It was not the fault of the petitioners that the Commission and/or the Government did not follow its own policy of following its decision regarding lower qualifying marks for the candidates belonging to backward

WEB COPY
NOT OFFICIAL

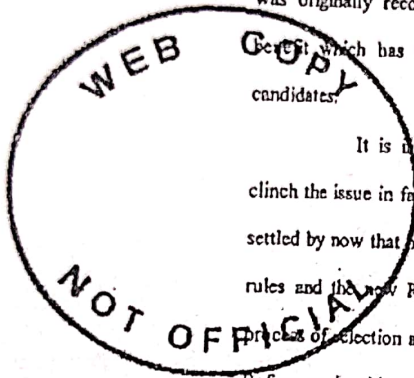
6/7

25

category and therefore, if the Government and the Commission had to be directed by this Court in the case filed by the similarly situated persons for drawing a fresh merit list, and in such merit list the name of the petitioners had figured above someone who was originally recommended, they cannot be deprived of the benefit which has been given to the originally recommended candidates.

It is in fact this aspect of the matter which would clinch the issue in favour of the petitioners inasmuch as it is well settled by now that old vacancies have to be governed by the old rules and the new Rules coming into force after beginning of process of selection as per old Rules cannot be made applicable.

Reference in this connection may be usefully made to the judgment of Apex Court in the case of P. Mahendran Vs. State of Karnataka reported in (1990) 1 SCC 411. Moreover a right to receive pension is condition of service as has been held by the Apex Court in the case of Union of India Vs. Gurnam Singh reported in (1982) 2 SCC 314 and thus to be governed in accordance with the terms and condition of the advertisement and the existing Rules inasmuch he acquires a right to be considered for selection and appointment in accordance with the then existing Rules. This Court would accordingly hold that the petitioners being appointees of the old transaction of Advertisement No. 2 of 2000 in continuation with old appointees of 2003 will be entitled to get the benefit of old pension scheme and they will not be governed by the new Contributory Pension Fund Scheme coming



717

26

into force w.e.f. 1.9.2005. It has to be also kept in mind that even the original appointment letter issued on 26.11.2005 to the petitioners, did not contain any clause and/or condition that they will be governed by the new Contributory Pension Fund Scheme and therefore, the resolution of the Finance Department, contained in Annexure 10 dated 1.9.2005, cannot be made applicable in the case of the petitioners as it was not made part of their service condition also in their appointment letter.

For all these reasons, this application is allowed and the respondents are directed to give benefit of old pension scheme under Bihar Pension Rules to the petitioners as was extended to other 41 Dug Inspectors appointed out of the same advertisement and transaction.

WEB COPY
NOT OFFICIAL

Surendra/

(Mihir Kumar Jha, I)

अनुक्रम 5 - 11

4 of 12

(19)

Filed through:

Abhay Shanker Singh, 29/01/2022
Abhay Shanker Singh, Adv.

AOR No. 01994

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

CWJC No. 2312 /2022

In the matter of an application under Article
226 of the Constitution of India

AND

In the matter of :-

Bihar Administrative Service Association through its General Secretary Sri
Anil Kumar, son of Late Raja Ram Singh, aged about 56 years, Male, having
its office at BASA BHAWAN, North of Income Tax Golamber, J.L. Nehru
Marg, Patna ----- Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through the Chief Secretary, Government of Bihar,
Patna
2. The Principal Secretary, Department of Finance, Government of Bihar,
Patna
3. The Principal Secretary, General Administration Department,
Government of Bihar, Patna
4. The Commissioner, Finance, Government of Bihar, Patna

5812
29

5. The Joint Commissioner, Accounts Administration, Department of Finance, Government of Bihar, Patna
6. The Bihar State Public Service Commission through its Secretary, Jawaharlal Nehru Road, Patna
7. The Accountant General, Bihar, Patna

--- --- Respondents

To

Hon'ble Mr. Justice Sanjay Karol, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion Justices at the said Court

Humble application on behalf of the aforesaid petitioner

Most Respectfully Sheweth:

1. That the petitioner Association beseeches indulgence of this Hon'ble Court for the following relief/s:
 - (a) For issuance of appropriate writ or writs in the nature of mandamus directing and commanding the respondent authorities to give benefit of old pension scheme under Bihar Pension Rules to the members of the petitioner association who had been appointed under 46th and 47th Batch of Bihar Administrative Service and further not to give effect to Clause 03 and Clause 06 of the Resolution No. 1964 dt. 31.08.2005 of the Finance Department, Govt. of Bihar and to lax the same with respect to them as they had been appointed under 46th and 47th Batch through advertisements published by the respondent Bihar Public Service Commission in February and November 2004 respectively, for the older vacancies of the year upto 2001-02, which was much before the cutoff

date of 01.09.2005 for the new contributory pension scheme and thus, they are entitled to old pension scheme and not with the new contributory pension scheme; under which they have been brought arbitrarily and discriminately by the respondent authorities.

(b) For any other relief or reliefs as the Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

2. That the issues of seminal importance raised in this writ petition are as follows:-

- i. Whether the members of petitioner association who were appointed in pursuance to advertisements published before 01.09.2005 under 46th and 47th batch for the older vacancies, are not entitled to old pension scheme and the Resolution of the government vide No. 164 dt. 31.08.2005 is not applicable to them?
- ii. Whether the members of petitioner association appointed in 45th and 47th batch of the BPSC are being covered under new pension scheme in most mechanical, arbitrary and unreasonable manner?
- iii. Whether non-inclusion of members of petitioner association appointed in 46th and 47th batch under the old pension scheme deprive them of their right as guaranteed under Article 14, 16, 21 and 300A of the Constitution of India?

3. That it is stated that the Petitioner is an Association of Bihar State Administrative Service Officers with Registration No. 663/2003 under Societies Registration Act, 1860 and this writ petition is being filed through its General Secretary in representative capacity because the issue raised herein affects all the members of the petitioner Association; so appointed through Advertisement for 46th and 47th Joint Competitive Examinations of BPSC and is of common interest.

7/1/12 (4/3)

4. That it is stated that the advertisement for appointment to the existing older vacancies of posts of Bihar Administrative Service, Bihar Finance Service, Bihar Education Service and Bihar Labour Service (General), Bihar Jail Service, Assistant Recruitment Officers etc. was published in the Hindi Daily Dainik Jagran, Hindustan and as well as English daily Times of India, Patna in February 2004 and 05.11.2004 respectively for 46th and 47th batch of Joint (Preliminary) Competitive Examination (those appointed through this are hereinafter referred as 46th-47th batch officers).

A copy of the aforesaid advertisements published in February 2004 and 05.11.2004 are annexed as Annexure-01 Series.

5. That it is stated that the Preliminary Competitive Examination of the 46th and 47th Batch for older vacancies were held prior to May 2005 (24.05.2005) and final results were published on 27.06.2007 and 24.01.2009 respectively.

A copy of the final result of 46th and 47th batch officers so published on 27.06.2007 and 24.01.2009 by BPSC, Patna is annexed as Annexure-2 Series.

6. That in respect of the 46th and 47th Joint Competitive Examination, following facts are pertinent to be considered:

- (i) The advertisements were published by the respondent Bihar Public Service Commission in February and November 2004 respectively for the older vacancies of the year upto 2001-02, which was made before the cutoff date of 01.09.2005 for the new contributory pension scheme.
- (ii) The Preliminary Tests were held prior to May 2005.

8/12
5
5/9

- (iii) The requisition for Bihar Administrative Service pursuant to 47th Joint Competitive Examination were sought by the BPSC vide Letter No. Letter No. 430, dt. 06.05.2005, again much before the cutoff date of 01.09.2005 for the new contributory pension scheme.
- (iv) The appointments against the older vacancies upto 2001-02 were covered under circular no. 502 dated 2-11-2002 of the Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Bihar (now GAD, Government of Bihar), as is evident from Letter No. 10059, dt. 10.11.2005 issued by the Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Bihar (now GAD, Government of Bihar)
- (v) At no point of time it was mentioned that they (selected appointees under 46th and 47th Batch) despite being appointed against old vacancies will be governed by the new contributory pension scheme made applicable with effect from 1-9-2005.

A copy of the Letter No. 10059 dt. 10.11.2005 issued by the Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Bihar (now GAD, Government of Bihar) is annexed as Annexure '03' to this writ petition.

7. That it is stated that in light of aforesaid, the older vacancies of the Bihar Administrative Service for the 46th and 47th Joint Competitive Examination were notified prior to the cutoff date of 01.09.2005 relevant for the new pension scheme and the process had begun under the old rules for the older vacancies and as such the old pension scheme shall be applicable for them.

8. That it is stated that under similar circumstances, some of the Drug Inspectors who were appointed after 1-9-2005 but pursuant to old advertisement and selection process had preferred a writ petition vide CWJC No. 10901 of 2006 claiming that they would not be covered by the resolution of government regarding applicability of new pension scheme to the effect that those appointed on 01.09.2005 and thereafter, shall have to be a member of newly contributory Pension fund scheme, and they claimed to be treated to have been appointed prior to dt. 01.09.2005 for pension purpose and the Hon'ble Court allowed the writ petition vide order dt. 03.08.2011 with observation that it is well settled by now that old vacancies have to be governed by the old rules and the new rules coming into force after beginning of process of selection as per old rules, cannot be made applicable.

9. That it is stated that the petitioner association has submitted a representation with details of facts and also the order of Hon'ble High Court dt. 03.08.2011 passed in CWJC No. 10901 of 2006 before the General Administration Department, Government of Bihar vide its Memo No. 21 dt. 13.07.2021, however, no decision has been taken and no order has been passed and still the members of petitioner association belonging to 46th and 47th batch are being deprived of their legal entitlement.

A copy of the aforesaid representation contained in Memo No. 21, dt.13.07.2021 is annexed hereto as Annexure '04' to this writ petition.

10. That it is submitted that as the advertisements were brought before the cutoff date 01.09.2005 and the process of selection was initiated under old pension scheme under Bihar Pension Rules, the members of petitioner association under 46th and 47th batch, are entitled to old pension scheme.

10.01.12 (7/9)
7

11. That it is submitted that the delay in the process of selection on account of litigation or otherwise cannot be attributed and made detrimental for the members of 46th and 47th batch selected BASA officers and it was only due to the procedural requirements and other exigencies on part of the respondents.
12. That the action/inaction on the part of the respondents is unjust, unfair and arbitrary and as such the same is violative of Article-14 of the Constitution of India.
13. That it is submitted that the deprivation of 46th and 47th batch officers of petitioner Association from benefits of old pension scheme under Bihar Pension Rules is violative of Article 14, 16, 21 and 300A of the Constitution of India.
14. That it is stated that the petitioner has not preferred any other writ petition for the relief /s prayed herein.
15. That it is stated that the petitioner does not have alternative efficacious remedy than to prefer this writ petition.

It is, therefore, prayed that your lordships be graciously pleased to admit the application issue Rule NISI calling upon the respondents to show cause as to why the reliefs prayed for above may not be granted and upon return of the rule and on such cause as may be shown and after hearing the counsel for the parties be pleased to make the same absolute.

~~11 d 12~~
8 (8/9)

And / or

Pass such order/orders as your lordships
may deem fit and proper in the given facts
and circumstances of this case.

And for this the Petitioner shall ever pray.

12/9/12 (99)

9

AFFIDAVIT

I, Anil Kumar aged about 56 Years, (Male), son of Late ~~Mr. Raj~~ Ram Singh, resident of Village-Sareyan Basnat, P.O - Rampur Kesho Annour P.S.- Taraiyan District -Saran, do hereby solemnly state and affirm as follows: -

1. That I am ^{General} Secretary of the Petitioner Association in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That the contents of this writ petition have been drafted under my instructions and I have read the contents thereof which I have fully understood.
3. That it is stated that the averments made under Para 3, 6P, 9P and 14 are true to the best of my knowledge and under Para 4, 5, 6P, 7P, 8 and 9P are true to best of my information and the rest are by way of submission before the Hon'ble Court.
4. That the annexure/annexures are true copy of the original's copy.

Anil Kumar

महसुब

विभाग प्रशासनिक सेवा
खिड़वा, पटना